GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
DEPARTMENT OF FERTILIZERS

**LOK SABHA**

**UNSTARRED** QUESTION **NO. 544** TO BE ANSWERED **ON: 04.02.2022**

**Storage of Fertilizers**

**544: SHRI RAMCHARAM BOHRA:**

Will the Minister of **CHEMICALS AND FERTILIZERS** be pleased to state:

(a) whether the Government proposes to use private warehouses to ensure adequate storage availability of fertilizers in the country;

(b) if so, the details thereof, State/UT-wise including Rajasthan;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the funds earmarked and the nodal agency, if any, appointed for the purpose?

**ANSWER**

MINISTER FOR HEALTH & FAMILY WELFARE AND CHEMICALS & FERTILIZERS
**(DR. MANSUKH MANDAVIYA)**

---

(a) to (c): No, Sir. Government has no proposal to engage private warehouses including Rajasthan for storage of fertilizers in the country. As per existing arrangements, fertilizers are distributed by State Governments through Markfed and dealers/ retailers network. These are stored at various points of supply chain according to the marketing strategy of respective companies in consultation with the State Governments.

(d): In view of above, question does not arise

XXXXXX

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित** प्रश्न संख्या **544**
जिसका उत्तर शुक्रवार, 4 फरवरी, 2022/15 माघ, 1943 (शक) को दिया जाना है।

## उर्वरकों का भंडारण

**544. श्री रामचरण बोहरा:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में उर्वरकों की पर्याप्त भंडारण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निजी भांडागारों का उपयोग करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और किस नोडल एजेंसी, यदि कोई हो, की नियुक्ति की गई है?

## उत्तर

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री**
**(डा. मनसुख मांडविया)**

---

**(क) से (ग):** जी नहीं। सरकार का देश में उर्वरकों के भंडारण हेतु राजस्थान सहित निजी गोदामों की सेवाएं लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मौजूदा व्यवस्थाओं के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा उर्वरकों का वितरण मार्कफेड और डीलरों/खुदरा विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकारों के परामर्श से विभिन्न कम्पनियों की विपणन कार्यनीति के अनुसार इनका भंडारण आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न केंद्रों पर किया जाता है।

**(घ):** उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

******